BJYM MAGAZINE

DECEMBER 2021

CONTENTS

1 संपादकीय

3 KT Jayakrishnan Master- Inspiration For Ever
-CR PRAFUL KRISHNAN

5 उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम: एक अध्ययन
-हिमांशु शर्मा

7 Indoctrination in Kashmir
-TOUSEEF RASOOL DAR

9 Women Entrepreneurship
-SANJANA

11 Re-defining the debates on anti-conversion laws
-YASHOWARDHAN TIWARI

14 Right to Education Act
-GAUTAM JHA, PANKAJ KUMAR

16 जनजातीय गौरव का राष्ट्रीय प्रतिष्ठापन
-पीयूष द्विवेदी

18 दासता के काल में भारतीय अर्थव्यवस्था को किया गया तहस नहस, अब भारतीयता के "स्व" को जगाना आवश्यक
- प्रहलाद सबनानी

20 The Transformation of Uttar Pradesh under Yogi Adityanath's leadership
-SHANTANU GUPTA

22 Mission Karmyogi: Integrating Academia in Capacity-Building for Civil Servants
-DR. AROON MANOHARAN, DR. POOJA PASWAN

24 Digital Innovation
-BHARAT PANCHAL

27 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने वाली शिक्षा नीति
-मिथिलेश कुमार पाण्डेय

Advisory Board

Abhinav Prakash
National Vice-President BJYM

Varun Jhaveri
National Incharge, Policy & Research BJYM

Editorial Board

Dr. Aditi Narayani Paswan

Saurabh Kumar Pandey

Adarsh Tiwari

Cover credit: Suchita Pande (twitter: suchita_p05)

संविधान दिवस

संविधान या विधान एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें किसी भी राष्ट्र की शासन सत्ता, प्रशासनिक व्यवस्था व कानून व्यवस्था का पूरा लेखा जोखा होता है. प्राचीन काल से ही राजतंत्र रहा हो या लोकतंत्र हर दौर मे संविधान एक आवश्यक दस्तावेज रहा है. संविधान के बिना हम किसी भी संगठित राष्ट्र की कल्पना भी नही कर सकते. जब बात भारतीय संविधान की हो तो बात बेहद खास हो जाती है. भारतीय संविधान भारत के हर नागरिक के लिए किसी पवित्र ग्रंथ जैसा है. संविधान बनने और बनाने के दौरान क्या कुछ हुआ ये भी जानना काफी रोचक है. संविधान के प्रति लोगों में और जागरूकता आये इसलिए सरकार ने प्रति वर्ष संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया.

संविधान दिवस एक ऐसा दिन जिस दिन हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया था. कुछ वर्ष पहले तक ये दिन महज सामान्य ज्ञान की किताबों में एक तिथि के रूप में सिमटा हुआ था. परन्तु साल 2015 में संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस दिवस को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाने के केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था. संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है.

हर भारतीय नागरिक के लिए हर साल 26 नवंबर का दिन बेहद खास होता है. यह संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश का आजाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है. जहां संविधान के दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं, वहीं इसमें दिए मौलिक कर्तव्य में हमें हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं.

26 नवंबर, 1949 को ही देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को अंतिम रूप से अपनाया था. हालांकि इसे 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था.

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे: नए भारत की नई रफ्तार

गाजीपुर में सब्जी की खेती करने वाला एक किसान अपने निकटतम मंडी में जाकर अपनी सब्जियां बेचता था. ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस लायक नही कि ज्यादा दूर जा सके दूसरे शहरों के मार्केट में जा सके विकल्प के अभाव में जहाँ उसे आसान लगता था वही उसी दाम में बेच के घर लौट आता था. लेकिन अब ऐसा नही होगा अब कोई किसान भोर में 4 बजे अपनी ताजी सब्जियां तोडकर गाड़ी में लादकर 4-5 घण्टे में लखनऊ जैसे शहर तक बड़ी आसानी से पंहुच सकता है. अपने मुताबि क अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है. सिर्फ किसान ही नही व्यापारी वर्ग जो अपने बिजनेस के सिलसिले में या कोई बीमार हो जो अच्छे उपचार के लिए राजधानी लखनऊ जाना चाहे. तो सुबह घर से निकलकर शाम तक अपने परिवार के बीच में पंहुच सकता है. ये संभव हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की वजह से जिसकी सौगात गत माह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लोगों खासकर पूर्वांचल के लोगों को दिया.

ये एक्सप्रेस वे लखनऊ से पूर्वी यूपी के शहरों को जोड़ता है. लखनऊ से गाजीपुर तक का यह 340 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे कई खासि यतों से लैस है. यहां फाइटर जेट उतारे जा सकेंगे और विकास को भी रफ्तार मिल पाएगी. पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में कहा कि यह यूपी के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने का काम करेगा. इस एक्सप्रेसवे से एक तरफ यूपी में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो वहीं बिहार के बक्सर से लखनऊ तक का सफर महज 4 घं टे में ही तय हो सकेगा, जिसमें अभी 7 से 8 घं टे तक लगते रहे हैं.

इस एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ से यूपी के मऊ, गाजीपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी जैसे जिले आसानी से और सीधे जुड़ सकेंगे. इससे किसानों को फसलों को ले जाने और कारोबार में मदद मिलेगी. पीएम नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला आजमगढ़ में 2018 में रखी थी. महज तीन

साल में इसे पूरा करके योगी सरकार ने प्रोजेक्ट की गति दिखाई है. जो यह दर्शाता है कि ये नए भारत की नई रफ्तार है. इससे देश की छवि बदली है. जहाँ पहले प्रोजेक्ट सालों तक अटके रहते थे. वही अब अत्याधुनिक व विश्वस्तरीय एक्सप्रेस वे समय से पहले बनकर जनता को समर्पित किया जा चुका है. इस एक्सप्रेसवे को तैयार करने में कुल 22,500 करोड़ रुपये की लागत आई.

छह लेन के इस एक्सप्रेसवे पर यदि कोई वाहन 100 किमी प्रति घण्टे की रफ्तार से भी चले तो गाजीपुर से लखनऊ तक का सफर महज 3.5 घंटे में ही तय करा देगा. इस एक्सप्रेसवे पर कुल 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ब्रिज, 7 लंबे पुल, 104 छोटे पुल, 13 इंटरचार्ज और 241 अंडरपास भी मौजूद हैं. जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि आसपास के निवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कितना उत्तम प्रबन्ध किया गया है. यह उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अब तक का देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है.

आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जब दुनिया के कई देश विकास के मामले में आधारभूत संरचना के मामले में हमसे आगे निकल रहे थे. तब पूर्ववर्ती सरकारों का ध्यान इन कामों पर कम और राजनीति करने पर ज्यादा था. परन्तु अब भारत का भारतीयों का माइंडसेट बदला है. अब ये नया भारत नई कार्यसं स्कृति के साथ दुनिया के सभी बड़े देशों के साथ कदमताल करते हुए विकासशील से विकसित होने के क्रम में तेजी से रफ्तार पकड़ चुका है. जो काम सालों पहले हो जाना चाहिए था वो अब हो रहा है. तो ऐसे में उम्मीद है. भारत की विकास यात्रा में ऐसे एक्सप्रेस वे अपनी महती भूमिका निभाएंगे. और एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को और मजबूत करेंगे. पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भेदभाव रहित व समावेशी विकास का एक अनुपम उदाहरण है. जो अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति को सीधा लाभान्वित करेगा.

त्रिपुरा की जीत बीजेपी के लिए शुभ संकेत है

कोरोना की दस्तक के बाद से देश के अलग-अलग हिस्सों में संपन्न हुए सभी स्थानीय निकाय के चुनावों, उप-चुनावों तथा विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है चाहे वह उत्तर प्रदेश में हुए उप-चुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव हों, गुजरात के उप-चुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव हों, असम में हुए उप-चुनाव हों, जम्मू-कश्मीर के बीडीसी इलेक्शन हो, हैदराबाद का जीएचएमसी इलेक्शन हो, मणिपुर, तेलं गाना और कर्नाटक के उप-चुनाव हों या अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुए स्थानीय निकाय के चुनाव हों – सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासि क जीत मिली है। आजादी के बाद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की जो सरकार त्रिपुरा में बनी है, उसका प्रभाव जन-जन तक देखने को मिल रहा है। यह विजय मोदी जी के सरकार की लोक-कल्याणकारी नीतियों में लोगों के पूर्ण विश्वास का परिचायक है।

इस चुनाव ने साबित कर दिया कि त्रिपुरा में वामदलों का अब कोई जनाधार नही बचा है. वे अपना अस्तित्व और प्रासंगिकता खो चुके हैं. बंगाल चुनाव में भारी जीत से अति आत्मविशवास से लबरेज होकर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी इस चुनाव में जोर शोर से अपनी भागीदारी की. लेकिन त्रिपुरा में उन्हें चारों खाने चित होना पड़ा. टीएमसी का त्रिपुरा में सूपड़ा साफ होना ये दर्शाता है कि बंगाल के बाहर उनका कोई जनाधार नही है. ये ममता बनर्जी के उस दावे को भी खारिज करता है जिसमे गाहे बगाहे वो विपक्ष को नेतृत्व प्रदान कर प्रधानमंत्री बनने के सपने संजोती हैं.

अगर बात आंकड़ों की करें तो भाजपा ने 222 सीटों में से 217 सीटों पर जीत हासिल की है. विपक्ष के पास बस 5 सीटें गयी हैं. हालांकि इस चुनाव से पहले राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता त्रिपुरा को लेकर कई भ्रामक खबरे प्रचारित कर रहे थे. त्रिपुरा को अल्पसं ख्यक समुदाय के लिए असुरक्षित बता रहे थे. तुष्टिकरण के क्रम में उन्होंने त्रिपुरा के हिंदुओं को दंगाई तक बोला. लेकिन अब चुनावों के परिणाम से साफ हो गया है कि ये तुष्टिकरण करण की राजनीति त्रिपुरा की जनता से नकार दिया. वहाँ के बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक समुदाय ने मिलकर बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई है. त्रिपुरा निकाय चुनाव का ये परिणाम बाकी राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए एक शुभ संकेत है.

KT Jayakrishnan Master- Inspiration For Ever

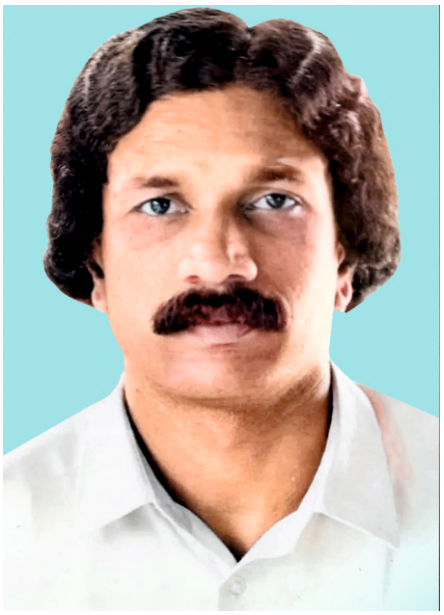

ഭാരതീയ ജനതാ യുവമോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷനായിരുന്ന കെ.ടി. ജയകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററെ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കേ പാനൂർ ഈസ്റ്റ് യുപി സ്ക്കൂളിലെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ കയറി പിഞ്ചു കുട്ടികളുടെ മുന്നിലിട്ട് അരുംകൊല ചെയ്തിട്ട് 22 വർഷം പിന്നിടുന്നു. 1999 ഡിസംബർ ഒന്നിനായിരുന്നു ലോകം മറക്കാത്ത, സമാനതകളില്ലാത്ത പൈശാചികമായ ആ ക്രൂരകൃത്യം സിപിഎമ്മിന്റെ ഉന്നതതലഗൂഢാലോചനയോടെ നടപ്പായത്. യുവമോർച്ചയെ ശവമോർച്ചയാക്കുമെന്നും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ചും ബോംബുണ്ടാക്കുമെന്നും നിർലജ്ജം ആക്രോശിച്ച മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടേയും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടേയും പിന്തുണയോടെയാണ് ജയകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററെ വിദ്യാലയത്തിൽ കയറി വെട്ടിനുറുക്കിയതെന്ന് ഏവർക്കുമറിയാം. 1968 മുതൽ നൂറോളം പ്രവർത്തകരെയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് ആക്രമണങ്ങളിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്നു മാത്രം രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിനും സംഘ വിവിധക്ഷേത്ര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നഷ്ടമായത്. കേരളത്തിലാകമാനം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം പേർ ബലിദാനികളാകേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അതിൽ വലിയൊരു സംഖ്യ ഇന്നത്തെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നാടായ കണ്ണൂരിൽ നിന്നു മാത്രമാണെന്നത് അപമാനകരവും അപലപനീയവുമാണ്. 1968 ഏപ്രിൽ 28-ന് ജനസംഘം പ്രവർത്തകനായ വാടിക്കൽ രാമകൃഷ്ണനെ കൊല ചെയ്തു കൊണ്ട് സിപിഎം ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ നരമേധം.

രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘവുമായി ചേർന്നാൽ ഇതായിരിക്കും അനുഭവമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് താക്കീത് നൽകാനാണ് വാടിക്കൽ രാമകൃഷ്ണനെ അരുംകൊല ചെയ്തതെങ്കിൽ ജയകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ രാഷ്ട്രീയ വളർച്ചയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ അണി ചേർന്ന ജനതതിയേയും കണ്ടുള്ള അസഹിഷ്ണുതയാണ് ആ ക്രൂരകൊലപാതകത്തിന് സിപിഎമ്മിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. സംഘപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെറും കുത്തുമേറ്റ് അംഗഭംഗം സംഭവിച്ച നിരവധി പേർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രമുണ്ടെതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഭരണത്തിലുള്ളപ്പോൾ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചും ഭരണമില്ലാത്തപ്പോൾ പോലീസിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും പല സാഹചര്യങ്ങളുമൊരുക്കി സിപിഎം നടത്തുന്ന ഇത്തരം കൊലപാതകങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും പ്രതികരിക്കില്ലെന്നതാണ് സത്യം. കേസന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനും പ്രതികൾക്ക് സൈര്യവിഹാരം നടത്താൻ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതും മാർക്സിസ്റ്റ് അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അനുകൂലഘടകങ്ങളാണ്.

ജയകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ വധത്തിൽ കേരളത്തിലെ ബുദ്ധിജീവികളും നിയമപാലകരും കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ വടകരയുടെ മണ്ണിൽ വെച്ച് ഏതാണ്ട് അതേപോലെത്തന്നെ ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കൊലപാതകവും മറ്റും നടക്കുമായിരുന്നില്ല.

മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന കേരളമെന്ന കൊച്ചു ഭൂപ്രദേശത്ത് അവർ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ നേരിടുന്ന രീതിയാണോ ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ്. മാർക്സിസ്റ്റ് അക്രമ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ബംഗാളും ത്രിപുരയും രംഗത്തു വന്നതുപോലെ കേരളവും സജ്ജമാകുന്നു എന്നത് അവരെ വിറളി പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മുസ്ലീം തീവ്രവാദികൾക്ക് സഹായം ചെയ്ത് സംഘ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്നതാണ് കുറച്ചുകാലങ്ങളായുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പദ്ധതി. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്, എസ്ഡിപിഐ തുടങ്ങിയവരുമായി രാഷ്ട്രീയ ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട് സംഘപ്രവർത്തകരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമവും കേരളത്തിൽ ശക്തമായി നടക്കുന്നു.

എസ്എഫ്ഐക്ക് വേണ്ടി ഊണും ഉയിരും നോക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ച അഭിമന്യുവിന്റെ ഘാതകരുമായി ചങ്ങാത്തത്തിലേർപ്പെടാനും സിപിഎമ്മിന് ലജ്ജയില്ല. സിപിഎം തണലിൽ കേരളമിന്ന് മുസ്ലീം തീവ്രവാദത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഭീകരസംഘടനയായ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൽ അംഗങ്ങളാക്കപ്പെട്ട പലരും കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണെതും ഗൗരവത്തോടെ കാണണം. തൊണ്ണൂറുകളിൽ മുസ്ലീം ഭീകരവാദത്തിന്റെ നാവായി മാറിയ മദനിയുടെ പിഡിപിയുമായി സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും പൊതുസമ്മേളനവേദിയിൽ വച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പുണരുകയും ചെയ്തതും മെല്ലെ മെല്ലെ ഇന്ത്യാവി

Class Room in Mokeri East UP School, Kannur in which KT Jayakrishnan Master brutally murdered infront of his students

കുത്തൊഴുക്കും, രാഷ്ട്രദ്രോഹം നിറഞ്ഞ പല കുത്സിതവൃത്തികളും എൻഐഎയുടേയും സിബിഐയുടെയും പിടിയിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇന്നത്തെ കേരള ഭരണകൂടം നടത്തുന്ന ശ്രമം വളരെ വലുതാണ്.

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രം പാലക്കാട് മലമ്പുഴയിൽ വച്ച് എസ്ഡിപിഐ ക്രിമിനലുകൾ കൊല ചെയ്ത സഞ്ജിത്തിന്റെ കൊലപാതകികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. സഞ്ജിത്തിന്റേത് ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമല്ല, ലക്ഷണമൊത്ത തീവ്രവാദ ആക്രമണമാണ്. അന്തർ സംസ്ഥാന തീവ്രവാദ ബന്ധം ഈ കൊലപാതകത്തിനുണ്ട്. പട്ടാപ്പകൽ കൊല നടന്നിട്ടും പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി വാഹന പരിശോധന പോലും നടത്താതെ നിഷ്ക്രിയരായി നിന്ന പൊലീസ് സംവിധാനം ഭരണകൂട ഒത്താശയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. ഇടത് - ജിഹാദി കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഉണ്ടായ കൊലപാതകങ്ങൾ തന്നെയാണ് പാലക്കാടും ചാവക്കാടും ഉണ്ടായത്. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി തന്നെ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ബിജെപി ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്.

ഇന്ന് കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമൂഹിക അപചയങ്ങൾ നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ്. പിഞ്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ മുത്തശ്ശിമാർ വരെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മദ്യത്തിന്റെയും രാസ-മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗവും, വിൽപ്പനയും ഇവിടെ നിർബാധം നടക്കുന്നു. സിപിഎം, ഡിവൈഎഫ്ഐ ഭാരവാഹികൾ തന്നെ ഇത്തരം പല കേസ്സുകളിലും പ്രധാന പ്രതികളാകുന്നതും കേരളത്തിൽ സാധാരണ സംഭവമായിരിക്കുന്നു. എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകയായിരുന്ന അനുപമയ്ക്ക് നൊന്തു പെറ്റ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാൻ സമരം ചെയ്യേണ്ടി വന്നതും ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന ഇതേ കേരളത്തിലാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടിനെ ചെകുത്താന്റെ നാടായി മാറാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി മാർക്സിസ്റ്റ് അക്രമരാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെയും ഇടത് - ജിഹാദി കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരെയും ജനശ്രദ്ധ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് യുവമോർച്ചയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും നടന്നു വരുന്നത്.

കെ.ടി. ജയകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ വീരസ്മരണകൾ സംഘടനാ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് അടിയുറച്ച് നിന്ന്, രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളോട് സന്ധിയില്ലാത്ത പോരാട്ടത്തിലേർപ്പെടാനുള്ള പ്രചോദനമാണ് ഓരോ പ്രവർത്തകരുടെയും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാവനസ്മരണക്ക് മുന്നിൽ ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഡിസംബർ - 1 ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും റാലികളും യുവജനസംഗമങ്ങളും നടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ധീരബലിദാനത്തിൽ നിന്നും അജയ്യരായ ആയിരക്കണക്കിനു ജയകൃഷ്ണന്മാർ ഉയർന്നുവരുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്.

CR Praful Krishnan, President of BJYM Kerala offers floral tribute to Jayakrishnan master on his martyrdom day.

AUTHOR: CR PRAFUL KRISHNAN, PRESIDENT OF KERALA BJYM

उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम: एक अध्ययन

समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र का एक अभिन्न अंग रही है जिसका विरोध बिना अध्ययन कई राजनैतिक दलों द्वारा किया जाता रहा है। विरोध के तरीके यह बताते है कि विरोध का एक मात्र कारण समान नागरिक संहिता का भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में होना है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद-44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। समान नागरिक संहिता का संविधान में स्थान होना इस बात को साफ करता है कि समान नागरिक संहिता का विरोध करना भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र का विरोध हो सकता है, परन्तु यह भारत के संविधान का भी विरोध होगा। समान नागरिक संहिता का विरोध प्रायः इसके अनुच्छेद-25 के साथ टकराव का तर्क देकर किया जाता है। परन्तु इसे मात्र तुष्टीकरण की नीति से उपजा हुआ कुतर्क ही कहा जायेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद-44 तथा अनुच्छेद-25 का सह-अस्तित्व संभव है और अगर यह कहा जाए कि अनुच्छेद-25 के क्रियान्वन के लिए अनुच्छेद-44 का क्रियान्वयन होना आवश्यक है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम पारित करके ना केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद-25 के अन्तर्गत धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता को संरक्षित किया है, वरन् संविधान के अनुच्छेद-44 के क्रियान्वयन की दिशा में एक सार्थक कदम भी उठाया है। उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम का विरोध यूँ तो मुख्यतः अधिनियम का मुस्लिम विरोधी होना कहकर किया गया है। परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि समूचे अधिनियम में मुस्लिम शब्द का प्रयोग तक नहीं किया है। अधिनियम का अध्ययन यह दर्शाता है कि अधिनियम मुस्लिम विरोधी ना होकर दुव्र्यपदेशन, बल, प्रपीड़न, कपटपूर्ण साधन द्वारा तथा विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन का

विरोधी है। अधिनियम के माध्यम से उक्त प्रकार के धर्म संपरिवर्तन को दण्डनीय अपराध बनाया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दुव्र्यपदेशन, बल, प्रपीड़न, कपटपूर्ण साधन द्वारा तथा विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन को कम से कम एक वर्ष व अधिकतम 5 वर्ष के कारावास से तथा जुर्माना जो कि 15 हजार रुपये से कम ना हो से दण्डनीय किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि उक्त वर्णित संपरिवर्तन किसी अवयस्क, महिला या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के संबंध में कराया जाता है, तो उक्त संपरिवर्तन कम से कम दो वर्ष तथा अधिकतम दस वर्ष के कारावास व ऐसा जुर्माना जो कि 25 हजार रुपये से कम नहीं होगा से दण्डनीय किया गया है। उक्त प्रावधनों का अध्ययन स्पष्ट करता है कि जहाँ विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन का संबंध महिला, अवयस्क अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से है उन परिस्थितियों में कारावास व जुर्माना बढ़ाकर अवयस्क, महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को सशक्त करने का कार्य भी इस अधिनियम के माध्यम से किया गया है। अधिनियम के माध्यम से इस बात को आश्वस्त किया गया है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग तथा महिला बिना किसी भय के अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म का पालन कर सके तथा किसी भी प्रकार का दबाव व प्रलोभन उक्त जाति को धर्म संपरिवर्तन हेतु नहीं दिया जा सके। अधिनियम के प्रावधान धर्म संपरिवर्तन हेतु धर्म संपरिवर्तन की पूर्व घोषणा तथा धर्म संपरिवर्तन के संबंध में पूर्व रिपोर्ट को आवश्यक बनाते है। यह दर्शाता है कि अधिनियम धर्म संपरिवर्तन का प्रतिषेध न करके विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन को प्रतिषेध व धर्म संपरिवर्तन को निर्देशित व विनियमित करता है।

अधिनियम के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन को निर्देशित व विनियमित करने के साथ-साथ दुव्र्यपदेशन, बल, प्रपीड़न, कपटपूर्ण साधन द्वारा तथा विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन को निषेध किया गया है। अधिनियम के माध्यम से किसी धर्म विशेष से धर्म विशेष में संपरिवर्तन को निषेध नहीं किया, वरन् अधिनियम के प्रावधानों को सभी धर्मों पर समान रूप से लागू किया गया है। यही विशेषता अधिनियम को समान नागरिक संहिता के दायरे में लाती है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अध्येताओं द्वारा उक्त अधिनियम को समान नागरिक संहिता की दृष्टि से नहीं देखा गया। इसके साथ-साथ विरोधियों द्वारा अधिनियम का विरोध तो किया गया पर समान नागरिक संहिता के आधार पर उक्त अधिनियम का विरोध नहीं किया गया जो कि यह दर्शाता है कि समान नागरिक संहिता के विरोधियों को मात्र ''समान नागरिक संहिता'' शब्दों से घृणा है और समान नागरिक संहिता का विरोध मात्र इसके भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में होने के कारण किया जाता है। यह समान नागरिक संहिता के विरोधियों की उक्त विषय के प्रति गंभीरता को भी दर्शाता है। हास्यास्पद यह है कि उत्तर प्रदेश में विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लागू करके भारत के संविधान के अनुच्छेद-44 का क्रियान्वयन किया गया, परन्तु समान नागरिक संहिता के विरोधियों को भनक तक नहीं लगी।

लेखक: हिमांशु शर्मा
प्रदेशाध्यक्ष
भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान।

Indoctrination in Kashmir

Our neighbouring state, Pakistan has always acted in pursuance of its mala-fide intentions to knock down the edifice of tranquillity, and the future of the Kashmiri Youth. The state has been witnessing a trend of Pan-Islamism across the Kashmir valley due to Pakistan's double-dealing strategy and conspiracy, which has caused immense devastation to the state since the 1990s. The Hindu minority in the Kashmir valley fell victim to this and the Kashmiri youth was bent on laying down their lives in the name of "Jihad", the holy war. The separatist groups which were perceived as secular were abandoned by Pakistan, who favoured other Islamist substitutions when they started moving away from the Pakistani's stance to see Jammu and Kashmir merging with Pakistan.

Islamist terrorists have always endeavoured to bring about structural changes at cultural levels of the Kashmir society since the inception of militancy in the valley, and there was a rapid mushrooming of terrorist organizations and militants in Kashmir during the early 1990s which advocated for 'Nizam-e-Mustafa' (Rule of the Prophet) as the objective of their struggle. Simultaneously, all cinema houses, beauty salons, wine shops, bars, video centres, use of cosmetics, listening to music, or any such form of entertainment were banned by militant groups. Bans were imposed on the sale and purchase of cigarettes, and on the circulation of Indian national and Jammu-based newspapers in the Valley. Islamist groups threatened to bomb the houses of women who refused to wear veils. Such diktats bore a striking similarity to the restrictions that were imposed by the Taliban in Afghanistan and very recently by ISIS in Iraq & Syria. Various Islamist groups like Jamaat-e-Islami and its militant wing, Hizbul Mujahideen, the radical women's wing, Dukhtaran-i-Millat, Jamiat-ul-Mujahideen, Allah Tigers, Jamiat-ul-Ulemma Islam, Al Badr, Al Jihad Force, Al Umar Mujahideen, Muslim Mujahideen, Islamic Students League, Zia Tigers, and such organization's decreed the objective of their struggle as Islamization of the Socio-political and economic set-up, merger of Jammu and Kashmir with Pakistan and establishment of an Islamic Caliphate.

Religious radicalization has seen a growing influence in Jammu and Kashmir, and a vast majority of the Muslim youth in the Kashmir Valley is increasingly inclined towards extremist political, social, and religious ideas

repudiating and are bent upon challenging the status quo. There has been a sudden heave in Pan-Islamism in Kashmir's Muslim society which has gradually marginalized an initial pro-nationalist agenda of insurgency. Rabidly fanatical clerics are indoctrinating the youth with Wahhabi ideology, whereby they reject the old Kashmiri tradition of people visiting and paying obeisance at the shrines of popular saints (Sufis and Rishis), thereby terming it as a violation of the Islamic teachings.

The Kashmiri youth are often told that it is the duty of Muslims to capture the power and impose Sharia Law in society, which not only disapproves the idea of democracy but also legitimizes Jihad as means for establishing an Islamic Caliphate. These situations which play out in Jammu and Kashmir have posed a multitude of problems and challenges to our Brave Army Jawans who have been constantly working to put an end to the roots of Pakistani-based Jihadi groups like Hizbul Mujahideen, Harkat Ansar, Markaz Dawa-Wal-Irshad, and its militant wing Lashkar-e-Taiba which are extensively active in the Kashmir Valley, and constantly mislead the gullible people in Kashmir.

The destructive policies regarding Kashmir are trapping the youth and young intellectuals to pick up guns and fight against the Indian armed forces in the name of Jihad and has a devastating impact on their future and kills their parent's hopes and dreams for them. The outcome of every wrong is always punishment and like that the future of every terrorist is an encounter. The Army's jawans are always trying their best to catch the terrorists alive and reform their ideology in a bid to not only save their parent's hope but also the youth of Kashmir that is constantly led by multiple players. However, most of the terrorists refuse to surrender fearing the fate they and their family members would face at the hands of the Jihadists. While some parents may only have a single child who gets killed in an encounter, even then not a single person from the so-called Separatist groups will ever show any concern for the deceased terrorist's family members and their situation. Even though their son might have been dealt a painful death, their parents continue to live a life of longed suffered because their child was misled along the wrong path.

Nowadays, Islamic Militants are the new role models for the unemployed youth in Kashmir who are being made to believe that Muslims across the world are fighting and dying for them as a service to Islam. The disappearances of Osama bin Laden and Mullah Omar have been turned into myths and replaced by stories that Allah helped them to disappear, and these stories are used by Islamic clerics in Kashmir while preaching to the youth in mosques.

The Kashmiri education system has been destabilized due to the mushrooming growth of Madrassas which outpace the modern institutions of education. 'Jihad' is not only fought with arms and weapons in Kashmir now but, it also has a cyber dimension to it. Social media is used to glorify militancy and the ideological war is being fought on this new operational theatre with the help of web-based applications that allow the creation and sharing of messages. 'Electronic Jihad' includes activities such as the provocation to engage in terrorist activities and carry out violent attacks, radicalization, and recruitment of supporters, and carrying out a psychosomatic war aimed at increasing the enemy's vulnerability.

The Term jihad has often been misinterpreted and restricted to mean nothing more than a war, rather it should be understood from a universal humane perspective and its philosophical moral principles need to be taken into consideration for greater human and social welfare. It is the responsibility of every responsible citizen of Jammu and Kashmir, Media, civil societies, and most importantly the political leaders who have been acting as the corporal hosts of the State to educate the youth of the Valley and discourage them from idolizing militants, who are mostly victims of pseudo-religious eyewash and economic deprivation and, and it has become a necessity save the future of Kashmir from the destruction and devastation of Pakistan led policies.

AUTHOR: TOUSEEF RASOOL DAR "IS AN ACTIVIST FROM THE TANGMARG AREA OF JAMMU AND KASHMIR

Women Entrepreneurship

The liberalization of India's economy over the past three decades has created a wealth of opportunities for entrepreneurs looking to start and expand their businesses. Since the opening of the economy in the 1990s, entrepreneurial activity in the private sector has been largely responsible for the strong economic growth that has been experienced in the country. India is presently the world's third-largest source of start-ups and was ranked as the second most entrepreneurial country in the world in the recent Global Entrepreneurship Monitor (GEM) report, ahead of large economic powerhouses such as the United States, China, and the UK.

Entrepreneurship in India looks at the dynamic and changing nature of entrepreneurship in India. Women entrepreneurs are those women who think of a business enterprise, initiate it, organize, and combine factors of production, operate the enterprise, and undertake risks and handle economic uncertainty involved in running it. They may be defined as a woman or a group of women who initiate, organize, and run a business concern. Women Entrepreneurship has taken a spurt in India, over 1/3rd of the entrepreneurship ventures are owned by women of our country. Economic progress in terms of better education, urbanization, the spread of democratic culture, and most importantly society's recognition has immensely contributed to this growth.

Closer to home, Indian woman Entrepreneur Kiran Muzumdar Shaw, Chairman and Managing Director of Biocon Limited has received a plethora of corporate awards and civilian awards like Padma Shri (1989) and Padma Bhushan (2005) for her remarkable contribution to the health and medicine industry. Other famous Indian Women entrepreneurs include personalities like Vandana Luthra, Ekta Kapoor, Naina Lal Kidwai, and so on.

Special incentives and drives have been created in India to bolster the growth of women entrepreneurs. The government has launched various schemes to promote an entrepreneurial drive amongst women. The two pet schemes launched by our Prime Minister Shri Narendra Modi's government to support entrepreneurship and self-employment by helping set up micro-enterprises Pradhan Mantri Mudra Yojna (PMMY) and Stand-Up India launched in April 2015 and 2016 respectively — have proven to be the biggest beneficiaries that are provided to women.

Stand-Up India

The Stand-up India initiative was launched to encourage entrepreneurship at the grassroots level for economic empowerment and job creation. More than 81 percent, or 91,109 accounts, with a total value of Rs. 20,749 crores have been approved to women entrepreneurs under the Stand-Up India Scheme as of February 26, 2021. This scheme aims to make the institutional credit systems available to the underserved, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Women Entrepreneurs, to allow them to contribute to the nation's economic development. The aim of this scheme is to make bank loans between Rs.10 lakh and Rs.1 crore available to at least one Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST) borrower, as well as at least one-woman borrower, per SCB bank branch for the purpose of starting a Greenfield company. According to the data provided by the ministry of finance on February 26, 2021, over 81 percent of account holders were women.

"Govt should be complimented for making such gender-responsive policies, to galvanize the way for women entrepreneurship, and particularly for taking cognizance of women's role in the economy. We do know that 60 percent of Indian women are sitting at home and that needs massive awakening. The government has recognized this and it is the onus of business chambers such as ours to be the connecting dots to raise consciousness around schemes available,"

- Jahnabi Phookan, National President, FICCI Ladies Organization.

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PPYM)

On the 8th of April, 2015 the Pradhan Mantri Mudra Yojana (PPYM) was established to provide non-corporate, non-farm small/micro enterprises with

loans of up to the tune of Rs 10 rupees. Under PMMY, these loans are known as MUDRA loans. Commercial banks, RRBs, Small Finance Banks, MFIs, and NBFCs provide these loans. MUDRA has developed three products, 'Shishu,' 'Kishore,' and 'Tarun,' under the umbrella of PMMY, to represent the stage of growth and funding needs of the beneficiary micro unit/entrepreneur, as well as to serve as a useful point for the next step of growth. As per February 26, 2021, data, about 68 percent i.e., 19.04 crore accounts with an amount of Rs 6.36 lakh crore have been sanctioned to women entrepreneurs under the MUDRA scheme since inception. The scheme intends to give up to Rs 10 lakh loans to the non-corporate, non-farm small/micro enterprises classified as Mudra loans given by commercial banks, regional rural banks, small finance banks, microfinance institutions, and non-banking financial companies.

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY)

On August 28, 2014, Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) was launched to bring a large chunk of the population into financial literacy, access to credit and insurance benefits. By the 26th of Feb, 23.21 crore accounts out of the total 41.93 crore accounts opened under the scheme belonged to women. Narendra Modi said, "The way our sisters served the country through SHGs in Corona is unprecedented. Be it by making masks and sanitizers, delivering food to the needy, awareness work, the contribution of Sakhi groups has been incomparable in every way". Furthermore, he added that India has at least 420 million Jan Dhan bank accounts, of which 55% are in the name of women. He urged them to take full advantage of the government e-marketplace. It envisions universal banking access, with each household having at least one basic banking account, as well as financial literacy, credit, insurance, and pensions. PMJDY has provided the three social security programs through a platform. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), and Atal Pension Yojana (APY).

To kick start the initiative, the Prime Minister also participated in the **'Atmanirbhar Nari Shakti se Samvad'** program through video conferencing where he spoke to members of the women's SHGs associated with Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM). According to the PMO, DAY-NRLM aims to mobilize rural poor households to provide long-term support to improve their incomes and quality of life. The Prime Minister also mentioned that "To increase the scope of entrepreneurship among women, a big financial help has been released for more participation in the resolve of self-reliant India. Be it food processing enterprises, women farmer producers' association, or other self-help groups, more than ₹1,600 crores has been sent to lakhs of such groups of women". He also released Rs.25 crore as seed money for nearly 7,500 SHG members under the PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) scheme of the Ministry of Food Processing Industries and Rs.4.13 crore as funds to 75 Farmer Producer Organizations (FPO) under this mission.

The Finance Ministry released figures of women's participation in various schemes on eve of International Women's Day highlighting the gradual shift in the socio-economic conditions of women. The encouraging participation in government financial schemes meant they would be capable of managing their finances confidently and encouraged to make their own decisions.

Rural Development is not a one-time effort; it is an ongoing process. It is a big dream of Prime Minister Modi, which requires concerted team efforts from all stakeholders – the Government, financial institutions, the regulators, rural citizens, and the community at large. The current government has already come up with so many social and financial alleviation schemes for the poor, however, the fate of those who are unfortunate remains a concern. Until the implementation and evaluating agencies work out to find the best ways to measure the success or failure of any scheme and come up with ways to reach the target population, things will not change at all. One day we will encounter a situation where the maximum rural poor will be benefited under the various government initiatives through ICT and technological developments. Recently, after demonetization in India, many initiatives have been successfully implemented in rural India and rural people are more aware of how to access government benefits. The presence of an extensive system would also lead to a boost in the economy and would also help to enable the rural population to take a part in the growth of India.

AUTHOR: SANJANA,
A STUDENT OF DELHI UNIVERSITY

Re-defining the debates on anti-conversion laws

The debates on anti-conversion laws, whether from a social, cultural or a constitutional standpoint, often tend to boil down to a question of "ought" with a moral flavour. The points of contestation begin to revolve around the ethical content of religious conversion as an event and a process in and of itself, and the acts of conversion and proselytization are then judged on the touchstone of morality. The voices discussing religious conversions as cultural and historical phenomena somehow get drowned in this cacophony opposing the prohibition of proselytization. Even where historical accounts on conversion are taken into perspective, certain hegemonic narratives appear to take over which portray rosy images about the past where religious conversions were supposedly complex yet peaceful and harmonious processes rooted in the so-called 'Ganga Jamuni tehzeeb'. These narratives subdue the historical realities and alternative histories of Bharat's past, which expose religious conversions as much more inherently violent phenomena, crushing the latter under their "academic" weight. A re-examination of such marginalized alternative histories, a serious consideration and engagement with the arguments they put forth, is long due. Certain sections of the society, including scholars, might very well feel that this would open a Pandora's Box, drawing schisms and wedges within our society; so be it. While their concerns might be legitimate, nevertheless, this exercise is absolutely essential to get a holistic understanding of our history as a civilization.

The history of religious conversions in Bharat as a largely peaceful affair is based on at least three highly problematic arguments/assumptions: the non-theocratic, culturally accommodating nature of the pre-colonial states, little consciousness about religious identities among common people resulting in harmony among various faiths and the fluidity of religious identities during that era. Such an understanding betrays a lack of grasp of the intensity of religious identity formations during pre-colonial and colonial periods and resultant conflicts on the ground. The conventional understanding of mainstream historians has been very simplistic. It's indeed surprising (yet not so surprising) that such straightjacket viewings of our history come from the Left-Marxist nexus of historians who have established

themselves as the guardians of Indian historiography and have always emphasized on undertaking a deeply critical analysis of Indian history. Left's obsession with having a critical approach and prioritising problematisation of situations needs to be applied here. Dominant narratives need to be tested on the anvil of till date marginalized historiography which brings out the brutal nature of Islamic states in pre-colonial Bharat, sheds light on the formation of distinct Hindu and Muslim religious identities during that period, takes account of the horrors meted out by the Christian missionaries, provides deep insights into their logic of conversion and fresh identity formation, shows the violence involved in inter-religious interactions and religious conversions, the indigenous Hindu communities being mainly at the receiving end of it.

Independent India is often displayed as a fractured nation and a fissured society. One may note that any step towards reworking fissiparous tendencies and activities can't be taken unless we have established a nuanced yet crystal clear understanding of our own past. A society can't heal itself unless it reconciles itself to a truer and nuanced conception of its past. Any attempt at remedial hermeneutics requires a reconciliation with our history to heal our psychological wounds, address our trauma, have a better comprehension of our present and then chalk out the path to a sublime future.

At the cost of being a bit repetitive, it would be worthwhile to have a glimpse into some of the works of historians who have attempted to present alternative histories through rigorous scholarship.

A pathbreaking book in this regard has been written by the renowned historian, Padma Shri Dr. Meenakshi Jain. The book titled Parallel Pathways: Essays on Hindu-Muslim Relations (1707-1857) (published by Bhartiya Vidya Bhavan in 2010) is rich in evidence and argumentation and presents a very different perspective on Hindu-Muslim relations during the medieval era. It has argued that throughout the medieval period, the Muslim elite in India tried hard and did retain their links with the larger ummah. (p. 4) Even in the modern era, the Indian Muslims were preoccupied with the theories, languages and paradigms that have echoed and re-echoed during the entire Muslim history. (p. 6) Citing an instance of violence meted out to the Hindus, she quotes Amir Khusrau as such: "Whatever live Hindu fell into the King's hands was pounded into bits under the feet of elephants. The Musalmans who were Hindis (country-born) had their lives spared." (p. 4) A diverse set of characters ranging from court poets and historians, to Sufi saints and scholars emerge in this text with a strong Muslim consciousness and clear anti-Hindu stances. Dr. Jain sketches a lively narrative where these characters are found advocating the imposition of shariat and jizya, and encouraging cow-slaughter. The Naqshbandi Sufi Shaikh Ahmad Sirhindi proclaimed once, "Shariat can be fostered through the sword… The honour of Islam lies in insulting kufr and kafirs. One who respects the kafirs, dishonours the Muslims." (pp. 11-12) It is pertinent to note here that such proclamations often had a strong influence on state policies

and held considerable hold among the believing masses.

Hegemonic narratives about a largely peaceful "Indo-Islam" and mythical academic folklores prevalent on our prominent university campuses, weaved around a supposedly syncretic Hindu-Muslim culture before the advent of the British often fail to capture the other side of our medieval period, which Dr. Jain beautifully states as such:

"At the intellectual level, the resolve to maintain distance between the two faiths remained steady. Around A.D. 1645, Mihrabi wrote the Hujjat-al-Hind (The Indian Proof), to caution native converts from reverting to Hindu practices. Though acknowledging similarities between yogic practices and the Sufi path, Mihrabi condemned yogis as devoid of divine grace, an opinion the Sufis shared. Indeed any resemblances with Hinduism were vehemently denied. "Cultural apartheid" remained the exemplar in medieval Muslim India, "in default of cultural history"." (p. 14)

Reading and engaging with this extremely troubling history is essential precisely due to the reason that it challenges, and at times demolishes, several myths passed on under the garb of history. Sufi culture, considered as an epitome of India's syncretic culture and religious inter-mingling, then turns out to have a darker side where it overlaps and further the cause of fundamentalist Islam, i.e., conversion and genocide of the indigenous Hindu populations. Speaking of indigeneity, perhaps it's also time for our academic spaces to seriously consider researching on 'Middle Eastern coloniality' (for more on this, see India that is Bharat: Coloniality, Civilisation, Constitution) and its influence on Indian historiography and other social sciences.

At the intellectual, cultural and public levels, Hindu-Muslim relations seem to be have been stressed and violent as well. The gloomy clouds of conversion and loss of culture, the banality of state-sponsored barbarism, were dealt with by the people on a daily basis. As the monograph titled Becoming Hindus and Muslims: Reading the Cultural Encounter in Bengal 1342-1905 by intellectual historian Dr. Saumya Dey suggests, distinct religious identities as Hindus and Muslims were already in the process of formation during the medieval era, the Bengali folk poems and songs being a testament to it. These songs and ballads displayed a variety of anxieties, including that of conversion and of loss of one's religious identity and cultural lifeworld.

The entire point being that these lived realities of our wounded past need to be taken into consideration while understanding the contemporary issues of religious conversion and the controversy around anti-conversion laws such as "Love Jihad" laws. One is left awestruck by the deafening silence of certain intellectual and political sections on hate crimes such as Love Jihad despite the availability of considerable evidence to attest the claims. Similarly, the conversion tactics deployed by Christian missionaries amongst the vulnerable sections of Hindu society are barely contested. A prime reason is that a society spoon-fed on false history is condemned to an ignorant present and a doomed future.

Image credit: WavebreakMediaMicro

A unique research project developed for around 40 years on the comparative science of cultures by S.N. Balagangadhara has now contested the use of "religion" as a lens to study Indian culture. In his magnum opus, he has argued that religion itself is a Christian idea and hence doesn't adequately comprehend Indic culture and traditions, which are in dire need of a fresh theoretical framework to explain them. The constitutional debates around anti-conversion laws are duty-bound to address these arguments, acknowledge what the use of "religion" (along with a religious-secular divide) in Articles 25 and 26 of the Indian Constitution implies, explore its implications, and publicly describe what conversion and proselytization really entail.

With a massive spurt in the reportage of cases of Love Jihad, conversion rackets, religious hate crimes against lower caste Hindus, a rampant increase in missionary activities in geopolitically sensitive regions of India with ever increasing infiltration of radicalised Rohingyas and Bangladeshi Muslims, the need for having at least an anti-conversion law at the national level is being vehemently voiced. It shall bode well for the debates following the tabling of such a bill in Parliament to do the minimum favour of addressing our alternative, deeply painful histories.

AUTHOR: YASHOWARDHAN TIWARI IS AN LL.M. (GENERAL LEGAL STUDIES) CANDIDATE AND HAS PREVIOUSLY WORKED AS A GRADUATE RESEARCH IMMERSION PROGRAMME (GRIP) SCHOLAR AT JINDAL GLOBAL LAW SCHOOL.

Right to Education Act

In March 2021, the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) had submitted a detailed report on how the exemption under Article 15(5) of the Indian Constitution with respect to Article 21A had a strong impact on the educational opportunities that are available to children belonging to minority communities.

The NCPCR's report highlighted that around 62.50% of students in Minority Educational institutions belong to non-minority communities, and it was more than 70% in the states of Andhra Pradesh, Jharkhand, Punjab, Chandigarh, Chhattisgarh, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli, Delhi, Haryana, Madhya Pradesh, Puducherry, Rajasthan, Uttarakhand. In the absence of any clear guidelines regarding the minimum levels of enrolment of Minority students, the minority schools are catering only to 7.95% of the minority children population in the States. While schools being run by the Muslim community have more than 75% of the student population belonging to the Muslim Community, however, the figures of schools established by the Jains community is less than 20% and for the Sikh, Buddhist, Parsi, and Christian community, the figure is less than 30% respectively. Since Minority Educational Institutions are outside the net of the RTE Act, therefore many of them are deprived of good infrastructure, quality, and an adequate number of teachers, books, uniforms, and mid-day meals, etc. The Fundamental Right of Free & Compulsory education of lakhs of children (6-14 years) belonging to Minority Community is being violated by this exemption.

In November 2006, the Prime Minister's High-Level Committee for Preparation of Report on Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India, under the Chairmanship of Justice Rajindar Sachar, submitted its report which highlighted the poor socio, economic and educational status of the Muslim community.

The Fundamental Rights of free and compulsory education guaranteed under Article 21-A and recognized under the RTE Act must be made available to all children in the country irrespective of their religion. The right of a child should not be restricted only to free and compulsory education but should be extended to having quality education, without any discrimination on the ground of their economic, social, and cultural background. The State is required to treat all religions and religious groups equally, however, can make special provisions for women and children.

In a catena of Judgments that interference in matters of regulations is permissible, so long as that regulation is directed towards achieving educational excellence. In fact,

Image credit: smolaw11

the State has the power to make Regulatory measures even in respect of the Minority institutions.

In T.M.A. Pai Foundation and Ors. Vs. State of Karnataka and Ors., (2002) 8 SCC 481, where this Hon'ble Court at para 107 held as follows:

".... Any regulation framed in the national interest must necessarily apply to all educational institutions, whether run by the majority or the minority. Such a limitation must necessarily be read into Article 30. The right under Article 30(1) cannot be such as to override the national interest or to prevent the government from framing regulations in that behalf. It is, of course, true that government regulations cannot destroy the minority character of the institution or make the right to establish and administer a mere illusion; but the right under Article 30 is not so absolute as to be above the law."

The minority institutions do not want the RTE Act to apply to them in the garb of protecting the Minority Character of their institution as well as safeguarding their Right to establish and administer these institutions, however, they are admitting children belonging to non-minority communities, presumably for monetary gains and profit. It is important to highlight that there is not an adequate number of children belonging to the minority communities who are studying in these institutions. This defeats the very goal of achieving compulsory elementary education in the country. The Principles of Equity, Equality, and Justice for the children of our country merits that the law should be the same for all the citizens and there should not be any distinction in its applicability.

The goals of providing free and compulsory education to all children in age group six to fourteen would not possible if the Minority Institutions are completely kept outside the scope and ambit of the RTE Act. The underlying philosophy and the very objective of Articles 15(5), 29 & 30 is defeated since these so-called "Minority Educational Institutions" are not working solely for the welfare of students from minority communities but are operating to fulfil their ulterior motives. We feel upon consideration of a catena of Judgments of the Honourable Supreme Court of India, Sections 1(4) and 1(5) of the RTE Act are Ultra vires to Article 14 and 21-A of Constitution of India since they Deprive Educational Excellence to children belonging to minority communities.

AUTHOR: GAUTAM JHA IS AN ADVOCATE ON RECORD, PRACTICING BEFORE THE SUPREME COURT OF INDIA. PANKAJ KUMAR IS A FORMER EXPERT ON MISSION TO THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR THE REFUGEES AND ADVOCATE, SUPREME COURT OF INDIA.

जनजातीय गौरव का राष्ट्रीय प्रतिष्ठापन

अगले वर्ष भारत अपनी स्वाधीनता के पचहत्तर वर्ष पूरे करने वाला है। देश भर में अभी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव के इस अवसर पर हमें देश के उन अमर सपूतों का स्मरण अवश्य करना चाहिए जिनके संघर्षों और बलिदानों के परिणामस्वरूप भारत परतंत्रता की बेड़ियों को काटकर स्वतंत्रता प्राप्त कर सका। इतिहास में स्वतंत्रता के अनेक नायकों का वर्णन मिलता है, परन्तु बहुत से ऐसे नायक भी हैं, जिनके साथ इतिहास न्याय नहीं कर सका है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के इस दौर में देश के ऐसे गुमनाम नायकों को सामने लाकर उनके महान योगदान को आमजन के समक्ष रखते हुए उन्हें समुचित सम्मान देने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में जनजातीय नायकों के योगदान को रेखांकित करते हुए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई है। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने रांची में एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसके अलावा भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का शुभारम्भ भी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इस स्टेशन का नाम हबीबगंज हुआ करता था, लेकिन अब इसे नए नाम और विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ शुरू किया गया है।

रानी कमलापति की बात करें तो 18वी शताब्दी की गोंड रानी थीं। कहते हैं कि वे किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत थीं। गिन्नौरगढ़ के मुखिया निजाम शाह से उनका विवाह हुआ था। लेकिन निजाम शाह के भतीजे ने धोखे से अपने चाचा की हत्या कर दी। उससे रानी और उनके बेटे को भी खतरा था। ऐसे में रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह को गिन्नौरगढ़ से भोपाल स्थित महल ले आईं। रानी कमलापति अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थीं। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके पास न तो फौज थी और न ही पैसे थे। मगर तब भी अपनी सूझबूझ और साहस से रानी ने 'दोस्त मोहम्मद खान' से सहायता लेकर अपने पति की हत्या का बदला लिया। लेकिन जब उन्हें लगा कि दोस्त खान उन्हें अपने हरम का हिस्सा बनाने की मंशा रखता है, तो उन्होंने भोपाल के छोटे तालाब में अपने उतरकर जलसमाधि ले ली लेकिन मोहम्मद के सामने समर्पण नहीं किया। वे भोपाल की अंतिम हिन्दू रानी थीं। दुर्भाग्यवश इस महान वीरांगना को आजाद भारत में भुला दिया गया मगर अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखकर मोदी सरकार ने इस भूल को सुधारने का काम किया है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय समाज के योगदान को रेखांकित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, "जनजातीय समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया और अगर बताया भी गया तो बहुत ही सीमित दायरे में जानकारी दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज़ादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई, उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी... गोंड महारानी वीर दुर्गावती का शौर्य हो या फिर रानी कमलापति का बलिदान, देश इन्हें भूल

नहीं सकता। वीर महाराणा प्रताप के संघर्ष की कल्पना उन बहादुर भीलों के बिना नहीं की जा सकती जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी और बलिदान दिया।"

प्रधानमंत्री के इस कथन के आलोक में विचार करें तो स्पष्ट होता है कि वास्तव में, स्वतंत्रता के पश्चात् देश का शासन तो बदल गया लेकिन सोच बहुत अधिक नहीं बदली। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू मार्क्सवादी आर्थिक नीतियों को तो देश के उद्धार का एकमात्र उपाय मानते ही थे, नेहरूवियन मॉडल में अकादमिक जगत में भी मार्क्सवादी विचारधारा का ही बोलबोला होता गया। देश के शुरुआती पांच शिक्षा मंत्रियों में से चार का 'समुदाय विशेष' से ताल्लुक रखना क्या सिर्फ एक संयोग था या कांग्रेस के नेहरू प्रणीत सेकुलरिज्म का प्रयोग ? अब जो भी हो, लेकिन सच तो यही है कि स्वतंत्र भारत को जिस प्रकार से अपने गौरवशाली अतीत और महान नायकों को इतिहास-बद्ध कर बच्चों और युवाओं तक पहुंचाना चाहिए था, वैसा कुछ नहीं हुआ। अपितु इतिहास में विदेशी आक्रान्ताओं का महिमामंडन किया गया। रानी कर्णावती द्वारा भेजी राखी की लाज रखते मुगल आक्रान्ता हुमायूँ का ऐतिहासिक अर्धसत्य पढ़ाया गया। घास की रोटी खाकर भी पराजय ना स्वीकारने वाला महाराणा प्रताप की गाथा को कुछ पन्नों में समेट दिया गया तो वहीं बर्बर अकबर को 'अकबर महान' लिखकर इतिहास की किताबों के जरिये देश के बच्चों के दिमाग में भरा गया। देश के लोग अपने अतीत पर गर्व न कर सकें, इसके लिए अंग्रेजों द्वारा गढ़े गए 'आर्य आक्रमण सिद्धांत' के असत्य को स्वतंत्र भारत के मार्क्सवादी इतिहासकारों ने भी जोरशोर से आगे बढ़ाया। और तो और, रामायण और महाभारत जैसे भारत के स्वर्णिम इतिहास के अनुपम ग्रंथों को मिथक कहकर व्याख्यायित किया गया। ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं, जो कांग्रेसी शासन में इतिहास के विरूपण को स्पष्ट करते हैं।

बहुत अधिक पीछे न जाते हुए यदि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को ही देखें तो इसके लेखन में भी बहुत गड़बड़ी की गई है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इतिहास में 'गदर' या 'सैनिक विद्रोह' ही कहलाता रह जाता, लेकिन हमें आभारी होना चाहिए महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर का कि उन्होंने इसे देश का प्रथम स्वातंत्र्य समर कहते हुए इसका प्रमाणिक इतिहास लिखा। बीसवीं सदी के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भी कम गड़बड़ी नहीं की गई है। इस इतिहास में कांग्रेस व उसके नेताओं का इतना अधिक प्रभाव है कि उसके आवरण में देश के विविध हिस्सों में स्वतंत्रता के लिए अपने-अपने स्तर पर संघर्ष करने वाले बहुत से महान नायक छिप गए हैं। यह ठीक है कि गांधी जी के नेतृत्व में उस समय कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयास इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, परन्तु बीसवीं सदी में स्वतंत्रता की लड़ाई कांग्रेस के अतिरिक्त भी अन्य बहुत से रूपों में लड़ी जा रही थी। कहीं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता की धुन के पक्के क्रांतिकारियों का दल लड़ रहा था, तो कहीं आजाद हिंद फौज के जरिये नेताजी स्वतंत्रता का संधान करने में जुटे थे। इसके अलावा देश के अलग-अलग क्षेत्रों में अपने-अपने ढंग से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले बहुत से नायक संघर्षरत थे। देश के जनजातीय समाज में भी स्वतंत्रता की चेतना बलवती थी और अपने जल, जंगल और जमीन के लिए हमारे आदिवासी भाई-बंधू भी प्राणपण से संघर्षरत थे। इन संघर्षों और आंदोलनों के अनेक नायक भी थे, जो इतिहास में गुमनाम ही रह गए।

बिरसा मुण्डा को तो आदिवासी समाज ने भगवान मान लिया तो उनके संघर्ष और योगदानों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बात भी होती है, लेकिन अनेक ऐसे जनजातीय नायक हैं जो आज भी गुमनामी के अँधेरे में कैद हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में बस्तर के आदिवासी समाज द्वारा अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध और अपने जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए सशस्त्र भूमकाल आंदोलन किया गया था, जिसका नेतृत्व गुण्डाधुर के हाथों में था। गुण्डाधुर के संगठन कौशल और आदिवासी समाज के साहस पर खड़े इस आंदोलन ने बस्तर रियासत में अंग्रेजी हुकूमत को लोहे के चने चबवा दिए थे। आमने-सामने की लड़ाई में मुँह की खाने के बाद अंग्रेजों ने छल से इस आंदोलन को तो कुचला लेकिन गुण्डाधुर को नहीं पकड़ सके। अंततः अंग्रेजों को गुण्डाधुर की फाइल इस टिप्पणी के साथ बंद करनी पड़ी कि, "कोई यह बताने में समर्थ नहीं है कि गुण्डाधुर कौन था..."। लेकिन दुर्भाग्य कि देश के ऐसे नायक से आज देश की बड़ी आबादी परिचित नहीं है। भूमकाल बीसवीं सदी का आंदोलन है, लेकिन इस दौर के आंदोलनों के इतिहास में इसकी चर्चा शायद ही कहीं हुई हो। इसी तरह 1857 के स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले निमाड़ के आदिवासी योद्धा भीमा नायक का नाम भी इतिहासकारों ने भुला दिया। सिदो-कान्हू, तिलका मांझी, वीर तेलंगा खड़िया, नीलांबर-पीतांबर आदि अनेक नायक हैं जिनके संघर्षों की दास्तान अनकही रह गई। यह केवल कुछ उदाहरण भर हैं, वास्तव में आदिवासी क्रांतिकारियों और नायकों की सूची बहुत लम्बी है जिन्होंने देश को स्वाधीनता संग्राम में अपने-अपने स्तर पर संघर्ष किया और बलिदान दिया है, लेकिन इतिहास में उसके अनुरूप जगह नहीं पा सके। अब मोदी सरकार के प्रयासों को देखकर लगता है कि शायद देश के ऐसे आदिवासी योद्धाओं को उनका समुचित सम्मान प्राप्त हो।

बात केवल इतनी ही नहीं है, बात जनजातीय समाज के प्रति देश के बहुसंख्य नागरिकों के नजरिये में बदलाव लाने की भी है। आज जिस तरह तमाम लोग 'आदिवासी' शब्द का व्यवहार 'असभ्य' के अर्थ में करते हैं, यह सोच बदलनी चाहिए। जनजातीय समाज की अपनी संस्कृति, परम्परा और जीवनशैली है, उसे सम्मान से देखने का भाव भी आज की आवश्यकता है। 'जनजातीय गौरव दिवस' इस विषय में बड़े बदलाव का वाहक सिद्ध हो सकता है। सरकार के प्रयासों की धार यदि इसी तरह बनी रही तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय में जनजातीय गौरव का राष्ट्रीय प्रतिष्ठापन करने में सफल सिद्ध होंगे।

लेखक: पीयूष द्विवेदी
(कला-संस्कृति मामलों के जानकार)

दासता के काल में भारतीय अर्थव्यवस्था को किया गया तहस नहस, अब भारतीयता के "स्व" को जगाना आवश्यक

अभी हाल ही में ग्वालियर में आयोजित स्वर साधक शिविर में पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक माननीय डॉ. मोहन भागवत जी ने एक कार्यक्रम में कहा कि दुनिया विभिन्न क्षेत्रों में आ रही समस्याओं के हल हेतु कई कारणों से अब भारत की ओर बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। यह सब भारतीय नागरिकों में भारतीयता के "स्व" के भाव के जागने के कारण सम्भव हो रहा है और अब समय आ गया है कि भारत के नागरिकों में "स्व" के भाव का बड़े स्तर पर अबलंबन किया जाय क्योंकि हमारा अस्तित्व ही भारतीयता के "स्व" के कारण है।

परम पूजनीय सरसंघकचालक द्वारा कही गई उक्त बात भारत के आर्थिक क्षेत्र पर भी लागू होती है। भारत की आर्थिक प्रगति को यदि गति देनी है तो हमें भारत के नागरिकों में भारतीयता के "स्व" के भाव को बड़े स्तर पर जगाना आवश्यक होगा। देश के नागरिकों में भारतीयता के "स्व" को जगाने से हमारे नागरिकों में देश प्रेम की भावना जागृत होती है और इससे उनमें आर्थिक दृष्टि से तरक्की करने की भावना भी विकसित होने लगती है। जापान, इज़राईल, अमेरिका आदि देशों ने अपने नागरिकों में "स्व" की भावना को जागृत कर अपने देश की आर्थिक तरक्की में चार चांद लगाए हैं। इसके ठीक विपरीत, यदि किसी देश के नागरिकों में "स्व" की भावना नहीं है और उस देश पर यदि किसी विदेशी आक्रांता का शासनकाल स्थापित हो जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार तहस नहस हो जाती है इसका जीता जागता उदाहरण भारत रहा है।

Image credit: Natanaelginting

ईस्ट इंडिया कम्पनी के भारत में आगमन के पूर्व विश्व के विनिर्माण उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 1750 में 24.5 प्रतिशत थी, जो वर्ष 1800 में घटकर 19.7 प्रतिशत हो गई और 1830 में 17.8

प्रतिशत हो गई, आगे वर्ष 1880 में केवल 2.8 प्रतिशत रह गई तथा वर्ष 1913 में तो केवल 1.4 प्रतिशत ही रह गई थी परंतु वर्ष 1939 में कुछ सुधरकर 2.4 प्रतिशत हो गई थी। ब्रिटिश शासन काल में भारत के विनिर्माण उत्पादन को तहस नहस कर दिया गया था। इस सबके पीछे ब्रिटिश शासन काल की नीतियां तो जिम्मेदार तो थी हीं साथ ही भारत के नागरिकों में "स्व" की भावना का कमजोर हो जाना भी एक बड़ा कारण था।

1750 के आस पास, भारत सूती वस्त्रों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक था। कपास, लिनेन के भारतीय वस्त्रों तथा ऊनी सामानों का एशिया, अफ्रीका और साथ ही यूरोप भी बहुत बड़ा बाजार था। मुक्त व्यापार नीति ने भारत और ब्रिटेन के बीच कपड़ा व्यापार की दिशा को उलट दिया। सस्ते दामों पर इंग्लैंड से मशीन द्वारा निर्मित कपड़ों के भारी मात्रा में आयात ने भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा बड़ा दी। इसके अलावा, ब्रिटेन द्वारा भारतीय वस्त्रों के ब्रिटेन में आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। शीघ्र ही, भारतीय वस्त्रों पर सुरक्षात्मक शुल्क लगाने की ब्रिटिश सरकार की नीति के कारण भारत कच्चे कपास का निर्यातक और कपड़ों का आयातक बन गया।

भारतीय बाजार में ब्रिटिश सामानों के शुल्क मुक्त प्रवेश तथा निर्यातित भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों पर भारी करों ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया था। भारत में निर्मित हस्तशिल्प उत्पाद, घरेलू तथा विदेशी, दोनों ही बाजारों से लुप्त होने लगे थे। इसके अलावा, एक शिल्पकार के उत्पादों की तुलना में कारखानों में बने उसी प्रकार के उत्पाद सस्ते होने के साथ साथ गुणवत्ता की दृष्टि से भी बेहतर होते थे, जिसके फलस्वरूप भारतीय शिल्प उद्योग धीरे धीरे समाप्त होता चला गया।

भारत पर ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यूनाइटेड किंगडम में तो प्रति व्यक्ति आय में तेज वृद्धि होने लगी परंतु भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि धीमी होने के साथ ही नीचे भी गिरने लगी थी। भारत में वर्ष 1600 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (1990 अंतरराष्ट्रीय डॉलर में) 550 डॉलर था, जो वर्ष 1700 तक 550 डॉलर ही बना रहा वर्ष 1757 में गिरकर 540 डॉलर हो गया और वर्ष 1857 में 520 डॉलर हो गया। 1947 में जरूर थोड़ा सुधरकर 618 डॉलर हो गया था। वहीं दूसरी ओर यूनाइटेड किंगडम में वर्ष 1600 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 1600 में 947 डॉलर था जो वर्ष 1700 में 1250 डॉलर हो गया तथा 1757 में 1424 डॉलर होकर 1857 में 2717 डॉलर हो गया तथा 1947 में तो 6318 डॉलर हो गया।

इसी प्रकार, ब्रिटिश शासन के कार्यकाल के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर भी बहुत कम होती चली गयी वहीं यूनाइटेड किंगडम के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर बहुत तेज होती चली गयी। वर्ष 1600 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (1990 अंतरराष्ट्रीय डॉलर मिलियन में) 74,250 मिलियन डॉलर था यह वर्ष 1700 में बढ़कर 90,750 मिलियन डॉलर हो गया एवं वर्ष 1757 में 99,900 मिलियन डॉलर का हो गया तथा वर्ष 1857 में 118,040 मिलियन डॉलर हो गया तो वर्ष 1947 में 255,852 मिलियन डॉलर हो गया। अब यूनाइटेड किंगडम की स्थिति देखें। यूनाइटेड किंगडम में वर्ष 1600 में सकल घरेलू उत्पाद 6,007 मिलियन डॉलर था जो वर्ष 1700 में बढ़कर 10,709 मिलियन डॉलर हो गया तथा 1757 में 18,768 मिलियन डॉलर हो गया और वर्ष 1857 में 76,584 मिलियन डॉलर तक पहुंच कर वर्ष 1947 में तो 314,969 मिलियन डॉलर का हो गया।

ब्रिटिश शासन काल में न केवल भारत के अर्थतंत्र को तहस नहस किया गया बल्कि अंग्रेजों ने जाति और साम्प्रदायिक चेतना को उकसाते हुए प्रतिक्रियावादी ताकतों की मदद भी की थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी शासनकाल में, पश्चिमी सभ्यता के आगमन के फलस्वरूप ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां सक्रिय रूप में काफी व्यापक हो गई थीं। ये मिशनरियां ईसाइयत को श्रेष्ठ धर्म के रूप में मानती थी, और पश्चिमीकरण के माध्यम से वे भारत में इसका प्रसार करना चाहती थीं, जो उनके अनुसार धर्म, संस्कृति और भारतीयता के "स्व" में यहां के मूल निवासियों के विश्वास को नष्ट कर देगा। इस दृष्टि से ईसाई मिशनरियों ने उन कट्टरपंथियों का समर्थन किया, जिनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उनके अनुसार, भारतीय देशी संस्कृति और विश्वासों तथा भारतीयता के "स्व" को कमजोर करने वाला था। साथ ही उन्होंने साम्राज्यवादियों का भी समर्थन किया, क्योंकि उनके प्रसार के लिए कानून और व्यवस्था एवं ब्रिटिश वर्चस्व का बना रहना आवश्यक था। इसके साथ ही वे व्यापारियों और पूंजीपतियों के समर्थन की अपेक्षा भी रखते रहे क्योंकि ईसाई धर्मांतरित लोग उनके सामान के बेहतर ग्राहक होंगे और इस प्रकार भारत ब्रिटिश उत्पादों का एक बड़ा बाजार बन गया था। परंतु भारत में आज स्थितियां पूर्णतः बदल गई हैं। धीमे धीमे ही सही परंतु अब भारतीय नागरिकों में भारतीयता के "स्व" की भावना बलवती होती जा रही है। जिसके चलते अब भारत में आर्थिक विकास में भी गति आती दिखाई दे रही है।

लेखक: प्रहलाद सबनानी
(लेखक बैंकिंग क्षेत्र से सेवानिवृत्त हैं। आर्थिक विषयों के जानकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं)

The Transformation of Uttar Pradesh under Yogi Adityanath's leadership

In March 2017, when BJP named Yogi Adityanath as the Chief Minister after their landslide victory in UP, many political pundits wrote him off even before he took the oath of the CM's office. Analysts thought a saffron-clad mahant can only teach lessons in dharma and governance is not his cup of tea. This was a lazy analysis or hate for his saffron attire at best. 4.5 years in office – Yogi has proved them all wrong.

Uttar Pradesh, a state that used to be at the bottom of various development indices except for Crime under the governments of Akhilesh Yadav, Mulayam Singh Yadav, and Mayawati, has seen a wind of change with tremendous growth and achievements over the past four and a half years under Yogi Adityanath's leadership, and this is nothing short of a miracle given the short time span. Yogi Adityanath, who has been a five-time member of parliament, knew it was crucial to fix the law-and-order situation in the state and reinstate the trust of entrepreneurs and businesses, to bring a sense of prosperity to the state. Being the taskmaster that he is, he took the challenges head-on by increasing the ranks and file of the State Police Force by 1.5 Lakh Personnel and strategically bringing down gangsters, history sheeters within each district, and placed a strong emphasis on protecting businesses from land grabbers and extortionists. These factors along with the incentives that were provided to the industries for setting up their units in the state played a major role in the revitalization of Uttar Pradesh's industrial landscape and economy.

The improved Law and Order situation of the state resulted in it receiving investment proposals up to the tune of Rs 5 lac crores per annum and a large percentage of them saw groundbreaking ceremonies. In the past four and a half years, the State of Uttar Pradesh has jumped from the 12th to the 2nd spot in Ease of Doing Business Ranking since 2017, and it has outpaced several industrialized states such as Tamil Nadu, Maharashtra, and Telangana.

In addition to this, the state's fast-paced infrastructure development led to increased availability in power, and it also decluttered the red-tapism that the entrepreneurs used to face during the previous regimes, and this further lead to the creation of many jobs for the state's citizens. The State also conducted large-scale recruitments transparently and fairly, and it propelled the MSME through an innovative scheme like One District-One Product (ODOP), which further increased the overall jobs as a part of the government's employment drive under Yogi's leadership. As a result of this, the state's per capita income almost doubled and the unemployment rate dove to 4.1% in February 2021 as compared to 17.5% in 2017 when Akhilesh Yadav had just stepped out of office. It is because of these aforementioned factors that the State of Uttar Pradesh is now rapidly moving towards becoming the biggest economy within the country, and it has already jumped to 2nd position in Gross State Domestic Product (GSDP) from its 7th position under Akhilesh Yadav's leadership.

Prime Minister Modi's usage of the slogan 'double engine ki Sarkar' in his speeches during the state election campaigns in UP urged the people to vote the BJP into power so that it works in consonance with the government at the Centre and on the same frequency, but this was understood by the people to be nothing more than political rhetoric. However, Yogi Adityanath has proved it to be otherwise and that 'double engine' means 'double growth' for the states. The State of UP has worked in synchronization with the Centre, and they have implemented all the latter's development schemes efficiently and excellently while crossing all the required targets. Yogi has constantly brought senior cabinet ministers to the state to iron out pending issues and set larger targets that are to be achieved under his able leadership, which range from a multitude of fields ranging from the distribution of Gas Stoves to the construction of toilets and the construction of houses for the underprivileged, across which Uttar Pradesh has proven to be one of the top achievers.

Decoding the elements behind Yogi's success will provide us with some valuable life lessons. He was brought up in a hard working-class family, where his late father was known for his incorruptible reputation as a forest officer in Uttarakhand. During his tenure as a member of parliament from 1998 to 2017, he was among India's top-performing parliamentarians on the count of attendance, number of questions asked, number of debates participated in and number of private member bills presented.

During his two decades as a Member of Parliament, Yogi trained himself meticulously on governance and policy frameworks. He invested three to four hours every day in visiting the Janta-Darbars in Gorakhpur for the past 20 years, kept his ears close to the ground, and knew the pains and grievances of the people. In these two decades, Yogi also managed more than three dozen educational, health, and social institutions of the Gorakhnath Mutt, like a super CEO. While possessing such a rich wealth of experience and grounding, Yogi hit the ground running in 2017 and shook the slumber of Uttar Pradesh, catapulting it first amongst its equals within the past four and a half years. He transformed Uttar Pradesh from a that was counter under the BimarU States into one of India's most prominent and emerging Investment destinations.

AUTHOR: SHANTANU GUPTA, BIOGRAPHER OF YOGI ADITYANATH (PART 1: THE MONK WHO BECAME CHIEF MINISTER, PART 2: THE MONK WHO TRANSFORMED UTTAR PRADESH)

Mission Karmyogi: Integrating Academia in Capacity-Building for Civil Servants

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते

Whatever action a great man performs, common men follow. And whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues.

Bhagavad Gita, Chapter Three

There has been renewed focus on capacity building for India's civil servants. The Central government's "Mission Karmayogi" program has been envisaged as the most comprehensive bureaucratic capacity-building initiative that will empower government employees to become public servants who are more "creative, proactive, professional and technology-enabled". The focus of such reform is to enhance the administrative capacity and effectiveness of the public administration in India. This initiative, announced in 2020, will task the newly formed Capacity Building Commission, which is comprised of experts from multiple fields, with creating and then implementing capacity building plans.

What does "Mission Karmyogi" entail?

Mission Karmayogi has six pillars – Policy Framework, Institutional Framework, Competency Framework, Digital Learning Framework, electronic Human Resource Management System (e-HRMS), and Monitoring and Evaluation Framework. This ambitious effort has long been considered urgent given the need for greater capacity building among public administrators, many of whom have little formal training or qualification in core topics of administration and governance when they join the prestigious Indian Civil Services.

"Mission Karmyogi" challenges the steel frame of the past

The primary drive of this reform is to transform India's civil service system transition from a "rules-based" to a "roles-based" model so that it that can address the current capacity-related challenges of both rural and urban India. Over the years, many issues in governance and policy implementation can be attributed to any lack of robust and consistent training policies, unnecessary barriers to collaboration, and weak emphasis on continuous learning amongst civil servants. These are the effects of a rule-based approach that is itself a remnant of the colonial administration. In those days, new entrants were expected to develop skills from their supervisors rather than undergo any prior training. Such formal training was not considered necessary as the focus of the colonial administration was collecting revenue and maintaining law and order.

Challenges of Indian Civil Services post partition of India

In standards of public administration in India after it attained Independence from the British Raj was marred by severe political and social upheaval. Although the system was able to withstand the immense pressure on it because of the Second World War. However, partition had disastrous effects and the eventual division of the civil administration dealt a severe blow to its functioning and morale, which resulted in more than half the ICS officers either resigning or moving to service in Pakistan. This happened at a time when the nation needed administrative expertise, given the migration and violence that took place because of the country's partition. (Maheshwari, 1984). Perhaps the most important expectation of Indian public administration was its reorientation from a colonial administration to a "citizen" administration. Those who were once subjects, the public, became the new masters. It would be right to say that Indian public administration rose to the challenge and even exceeded many expectations (Maheshwari, 1984). There was broad-based support for this new "people" administration from across the political class, with national leaders expressing their confidence in the institution.

Reforms introduced post-Independence

The American academician, Paul. H. Appleby, who was invited by the government to study Indian administration, remarked that it was one of the most advanced governments with a broad constitution that was also open to feedback and improvement (Appleby, 1953). Based on his recommendation, the government established the Indian Institute of Public Administration (IIPA) in New Delhi to lead the transformation of its public administration into a people-oriented administration in the newly sovereign, democratic country. Such administration needed to instil public service values in its mission and vision and institutes such as the IIPA and LBSNAA were specifically focused on training administrators for that purpose. Our Nation's public administration education began in 1937 when the first diploma in public administration was granted at Madras University and this was soon followed by the establishment of the Department of Public Administration and Local Self-Government at Nagpur University in 1949.

What needs to be done?

Based upon the recommendations of the Administrative Reform Committee in 1966, the Administrative Training Institutes (ATI) was established with the aim of providing India's civil servants with the necessary competency and skills for administrators considering the changing nature of the state-centre relationships. The committee has laid a prime emphasis on the importance of continuous training throughout a civil servant's career hence there was a need for the ATIs had to understand the needs of civil servants at various levels of administration. More importantly, the ARC highlighted the role of academic institutions in the training and capacity building of civil servants, through lectures, seminars, discussions, which with the current remote facilities can surely be amplified across the nation.

In the current situation, the new entrants are not mandated or expected to have any prior degree or experience in the fields of public administration, public policy, or political science. However, even though the new entrants lack any formal education in the fields, the bulk of such knowledge is likely to be imparted during their preparation for the national civil service entrance examination. A vast majority of the students prefer to enrol themselves with preparatory institutions and coaching centres for the civil service examinations and they cannot be blamed for preferring the same over a formalized study of public administration and relation programs, since the latter is not widespread or popular.

Manoharan et al (2020) has found that the number of universities offering academic programs in public administration was an uncommon sight across the country and the students who had enrolled themselves in such programs were primarily focused on scoring well in the examinations, rather than equipping themselves with the necessary skills for future careers in public service. Furthermore, the author also observed that the syllabi and curriculum of such academic programs were heavily influenced by the syllabus and examination scheme of the civil service examination. Such a bold and ambitious effort would mean overhauling the entry and training of civil service officers in India. Those entering the civil services should have a wide range of educational backgrounds. But they often need the space to integrate their background with the workings of the administrative machinery.

Although the fresh civil service entrants are required to undergo initial training at various training institutes, it is pertinent to provide them with continuous training opportunities throughout their careers. The universities and colleges would be the government's most logical partners in providing continuous training and skill enhancement to the civil servants, and such departments must strengthen their academic programs related to public administration, public policy, public management, and related fields. Collaboration could lead to new courses that are relevant to the needs of the civil servants and provide opportunities for civil servants to interact with students.

The most promising avenues for potential academic collaboration would be with the Indian Institute of Public Administration (IIPA) and the ATIs. The IIPA was envisioned to be a leader and role model for training schools across the nation, and this was also reiterated by PM Vajpayee in his speech at the IIPA's Founder Day function in 1999; it was "…expected to actively participate in the training and retraining of civil servants in the art and science of Public Administration". The IIPA is based in the nation's capital, and the ATIs are in the state capitals. Together, they can collaborate with academic institutions to provide the structure for streamlining and strengthening the training of civil servants and increase their capacity to serve the public.

AUTHOR: DR. AROON MANOHARAN IS AN ASSOCIATE PROFESSOR AT THE MCCORMACK GRADUATE SCHOOL AT UMASS, BOSTON.
DR. POOJA PASWAN IS AN ASSISTANT PROFESSOR OF PUBLIC ADMINISTRATION AT JAMIA MILLIA ISLAMIA UNIVERSITY, NEW DELHI. SHE IS CURRENTLY AN ASSOCIATE OF THE NOVEMBER 2021 BATCH AT THE INDIAN INSTITUTE OF ADVANCE STUDY, SHIMLA
OUR GRATITUDE TO INDIAN INSTITUTE OF ADVANCE STUDY, SHIMLA FOR PROVIDING THE NECESSARY RESOURCES FOR THE ARTICLE.

References:
1)Appleby, Paul H. (1953). Public Administration in India: Report of a Survey (New Delhi: Cabinet Secretariat, Government of India).
2)Maheshwari, S. R. (1984). Strengthening administrative capabilities in India. Public Administration and Development, 4(1), 49-62.
3)Mission Karmayogi Booklet. Final Mission KarmYogi Booklet 22-2-21.cdr (dopt.gov.in)
4)Manoharan, A. P., Viswanath, S., & Sabharwal, M. (2020). Public administration pedagogy in India. Journal of Public Affairs Education, 26(3), 291-312.
5)Vajpayee, A. B. (1999). Indian administration today: Remedying its weaknesses. Indian Journal of Public Administration, 45(1), 1-4.

Digital Innovation

Image credit: robu_s

COVID-19 has been one of the toughest times since India attained Independence, and the second wave earlier this year was ferocious. It caught most people off guard; the spread of the virus accelerated at an incredible pace, leading to an impact to the public health system and on the overall economy so badly which in turn had impacted almost everyone in the country. During this unprecedented pandemic time, certain systems naturally failed since the need for supplies such as medical oxygen, PPE kits, etc was unprecedently high as compared to the past but we bounced back quickly to become Atma Nirbhar (Self-sufficient) within no time. India could respond well to all such challenges including the world's largest vaccination program right from the research, development, manufacturing, distribution of vaccine, and finally mass vaccination to more than 100 crore people of India in record time.

While that's a phenomenal achievement for us as a country, one important pillar which has played a major role during the pandemic to sustain our economy and daily routines for millions of people in Information Technology (IT), whose backbone which India has built during very recent times. What would have happened if this pandemic would have sometime around 2010? And just think for a moment that you were forced to reside inside your house for weeks and months due to lockdown, Work from a remote place, online education for children, ordering food, and other daily needs & services online? The digital platforms that have been utilized in the banking system, e-commerce platform, and online academic system were not even on the horizon during that time. Furthermore, the reach of mobile phones was very limited and internet speed was not a fraction of what is available today. Since all these were non-existent at that time, one can hardly imagine what would have happened to the common man and the overall economy and sovereignty of the country in such a terrible pandemic time?

As said by many visionaries in the past, the Twenty-first century belongs to India. Making this statement true, in the last two decades, India has witnessed two major revolutions which have helped us to elevate India's position as one of the strongest technological powerhouses in the world and this has helped us to stand strong despite this deadly pandemic time. The first one was the telecom revolution started in 2000 during the NDA government led by Shri Atal Bihari Bajpaiji which provided a lot of relaxation on spectrum availability, pro-business policies, incentive on new IT / Telecom infrastructure, etc. Progressing and

Image credit: Jekh

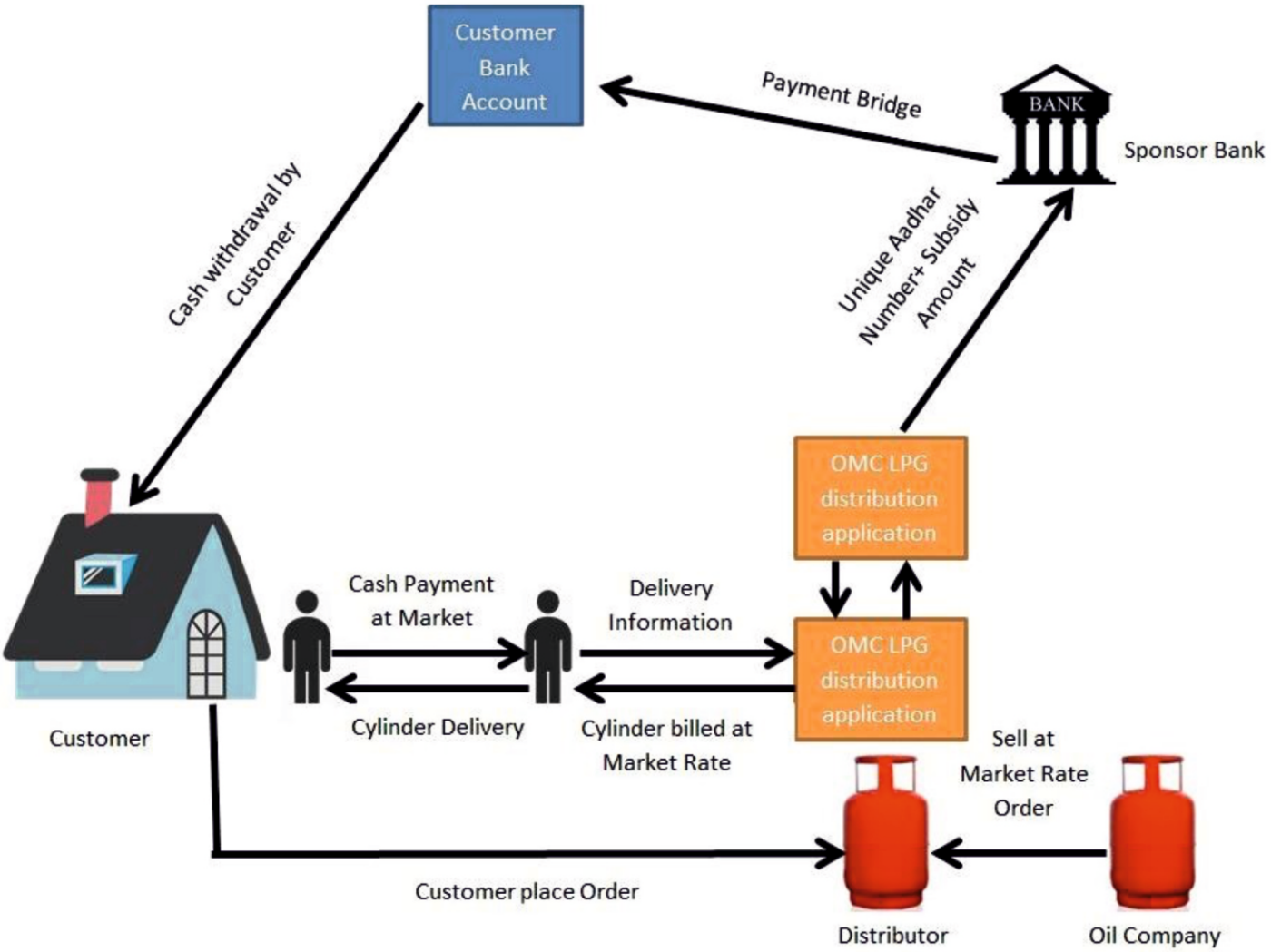

future-oriented steps were taken by the NDA government at a time when people used to wait for years and years post application to have a telephone line at their home or office. With this revolution, the mobile telephone became a necessity and part of life rather than merely being a luxury for a specific section of society. India spotted on the world's digital map for the first time with increased teledensity. It was due to this technological revolution that major technology giants started looking towards India as a great investment opportunity for IT and ITES, which resulted in a billion-dollar IT service industry that didn't exist earlier in India. This revolution also helped to lay down countrywide high-speed data and voice networks on which many of the initiatives later launched.

The second revolution was the digital revolution which has not only helped millions of lives in the pandemic but has made India much stronger. The revolutionary thinking of prime minister Shri Narendra Modi gave a very clear message to bring reforms relying on new-age technology when he made his first speech from Red Fort on 15th August 2014. The journey started to align his vision to make India digitally superpower. He announced a massive financial inclusion program "Pradhan Mantri Jandhan Yojana (PMJDY)" to bring maximum people into the digital banking system which has added 430 Crore people to the digital banking system in the last 7 years.

Now, look at the wonders what we have created in the last 7 years which is surely a matter of pride for any citizen. With over 25 billion transactions in the year 2020 and more than 3.65 billion transactions only on UPI (Unified Payment Interface) in September 2021, India has the most sophisticated and advanced payment platform which is way ahead in digital payments as compared to an equally populous country like China or a country with more advanced technology like the USA.

With over 1.29 billion digital identity Aadhar Cards issued, India has by far the largest and the best unique identity architecture in the world, based on biometrics and many more advanced features. Launched in 2016, India's

National Agriculture Market or e-NAM connects more than 17 million of India's farmers to a common national digital marketplace where they can trade in their Agri-produce. The Arogya Setu app, with over 190 million registered users became the world's most used mobile app in identifying, monitoring, and mitigating the spread of the COVID-19 pandemic.

Once former Prime Minister Late Shri Rajeev Gandhi said that out of one rupee spent by the government for the welfare of the downtrodden, only 15 paise from it reaches the people for whom it is meant. Where is this 85 paise going? Today, with more than 325 schemes and a cumulative transfer of more than $250 billion over 7 years, India has developed the world's best, leakage proof DBT (Direct Benefits Transfer) model.

JAM Trinity is the biggest reform for direct subsidy transfer to Indian citizens. With the outbreak of the COVID-19 pandemic and the imposition of lockdown and social distancing norms, DBT emerged as a boon in providing succor and relief to millions of citizens whose livelihood was impacted. The economic empowerment of citizens demands a continuous connection between the citizens and the government. Seamless integration between Jandhan, Aadhaar, and Mobile has helped in the Direct Benefit Transfer connecting the remotest corners of India which has revolutionized India's governance delivery.

Today, India has leapfrogged across markets that are more mature, to embrace new technological changes, as demonstrated by the adoption of mobile communications, smartphones, and apps. India's banking sector has made significant progress in moving towards a cashless economy. Moreover, India has also been a consistent source of intellectual capital, especially in technology, strengthening our case of "Make in India" towards the entire world. Engineers across the nation are developing next-generation software and technology that powers some of the world's most successful and innovative businesses and ideas.

As India is moving forward to become a vital engine of the world economy, so one will wonder how did this all happen? How did India emerge as the leader in the high technology domain despite its many perceived shortcomings and the everlasting historical baggage of being a developing nation?

Rome was not built overnight and neither was our digital revolution. It is pertinent to note that the true digital revolution started by the "Digital India" vision is perhaps the most successful initiative launched by Prime Minister Narendra Modi soon after he became the Prime Minister in 2014. He managed to achieve what could not be done for the last 70 years, within just 7 years, Digital India has become a symbol of empowerment for those who are left behind and those who innovate and make India proud with their innovations.

It reflects the vision of our PM in the true sense, in the year 2015 he had remarked that "Technology empowers the less empowered. If there is a strong force that brings a change in the lives of those on the margins it is technology. It (technology) combines 3Ss- speed, simplicity, and service. Technology is fast, technology is simple and technology is a brilliant way to serve people. It is also a great teacher. The more we learn about technology and the more we learn through technology, the better it is"

Digital India has changed the mindset and the cultural consciousness of the country and more importantly has brought huge transparency, be it in governance or businesses. It is after a very long time that Indians can now claim to create products and services that are original, replicable, world-class, and breakthrough technologies. Innovation through technology is part of the conceptualization of any scheme government thinks of today.

The automatic toll collection system FasTag is the best example of transparency, innovation, and efficiency. The digital revolution is not limited only to a few metros or few states but it is a pan-India phenomenon. The government and the private sector have found the perfect balance where the government creates the infrastructure and business-friendly regulatory policy which supports ease of doing business in India.

Any Indian who looks at how much we have progressed during the past seven years can proudly say that he dreamt of it, the nation made it. The entire Nation has joined hands to make the dream of a Digital India a reality. Youngsters are enthusiastic, the industry is supportive and the government is proactive. India has accomplished the mission of the digital revolution.

Author: Bharat Panchal is former chief of risk at NPCI.

Views expressed in this article are purely personal. The images used for representation purpose only.

भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने वाली शिक्षा नीति

किसी भी राष्ट्र अथवा समाज का सार्वभौमिक विकास तब तक सम्भव नहीं है, जब तक कि उस राष्ट्र तथा समाज की शिक्षा सतत् एवं गुणवत्तापूर्ण न हों, क्योंकि जिस प्रकार स्वस्थ मस्तिष्क के अभाव में स्वस्थ शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार सतत् एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव में परिपूर्ण एवं सशक्त राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जुलाई 2020 में लाई गई 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' भारत राष्ट्र के लिए सतत् एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक सुदृढ़ आधार के रूप में हमारे सम्मुख है। यह समझना आवश्यक है कि लगभग तीन दशक के बाद आई नई शिक्षा नीति राष्ट्र के सतत् एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कितनी आवश्यक है|

प्रथम दृष्ट्या यह जानने की आवश्यकता है कि आखिरकार हमें शिक्षा नीति में परिवर्तन के साथ-साथ नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका उत्तर निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है। पहला, व्याप्त शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार, अनुसंधान के साथ–साथ प्रबोधन को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की नितांत आवश्यकता थी। बदलाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब व्यवस्थाओं में समयानुकूल परिवर्तन होता है तो यह भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि यह बदलाव संतुलित हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने समाज में बदलाव के प्रमुख कारक शिक्षा को ही हाशिये पर रखा था। गौरतलब है कि वैज्ञानिक तथा तार्किक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में यह नई शिक्षा नीति सहायक साबित होगी। एक प्रमुख बिन्दु यह भी है कि भारतीय ज्ञान–विज्ञान तथा उसकी शिक्षण व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाने तथा उसकी गरिमा को सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा के वैश्विक मानकों पर भारतीय शिक्षण पद्धति का तालमेल बेहतर हो, इस दृष्टिकोण से भी हमें इसे देखना चाहिए।

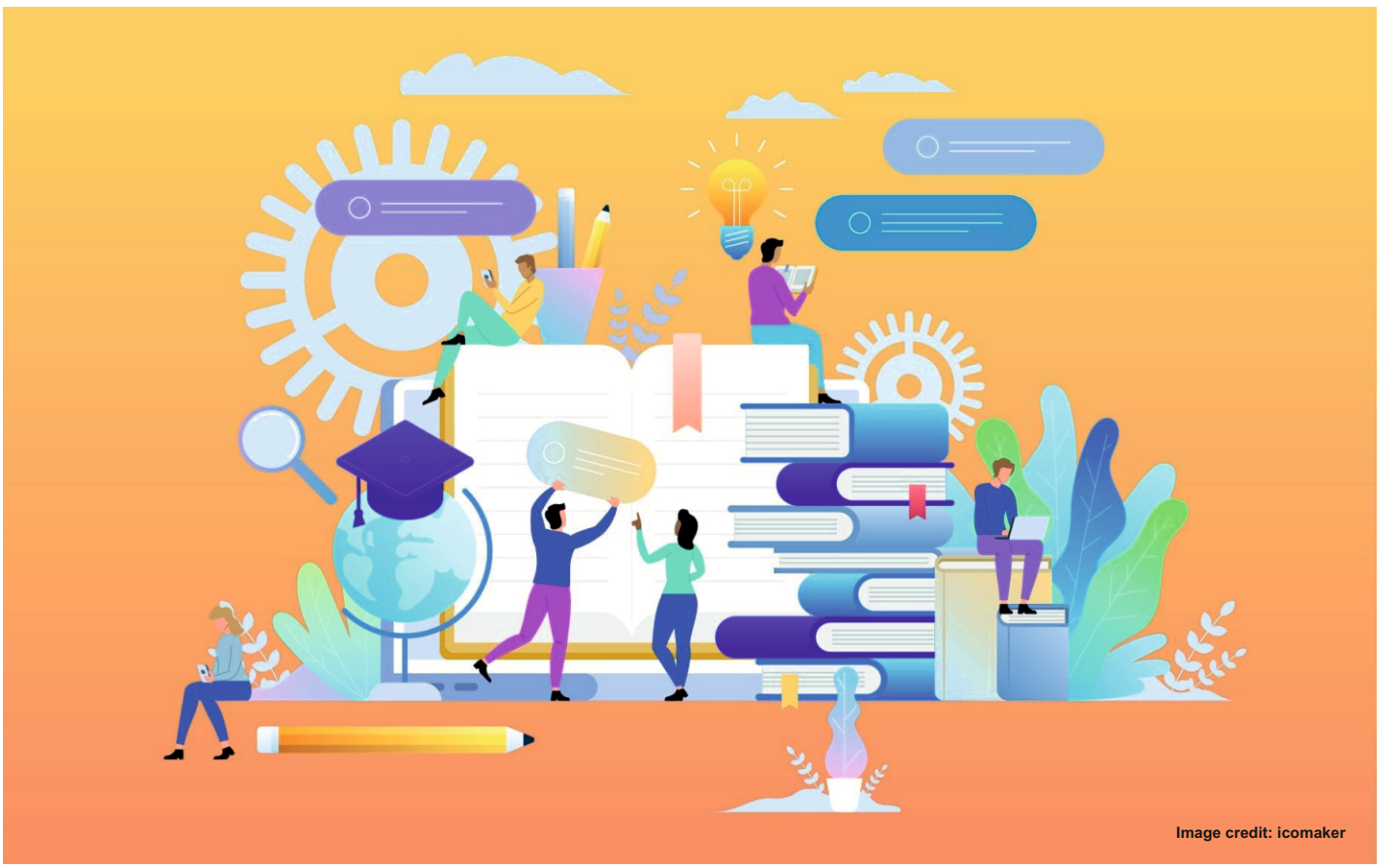

Image credit: icomaker

जब हम इन प्रमुख आवश्यकताओं को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमें तुरन्त शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही एक वृहद् राष्ट्रीय विचारों से पोषित संस्था 'भारतीय शिक्षण मण्डल' का ध्येय वाक्य याद आ जाता है, जिसका उल्लेख करना इसलिए आवश्यक है कि किस प्रकार ऐसी राष्ट्रीय विचारों से सिंचित संस्थाओं की दूरगामी सोच भारत की सतत् एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आधार बन सकता है -

"राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सम्पूर्ण शिक्षा को भारतीय मूल्यों पर आधारित, भारतीय संस्कृति की जड़ों से पोषित तथा भारत केन्द्रित बनाने हेतु नीति, पाठ्यक्रम तथा पद्धति में भारतीयता लाने के लिए आवश्यक अनुसन्धान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन और संगठन करना – भारतीय शिक्षण मण्डल का ध्येय वाक्य है"

वर्तमान सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के समक्ष प्रस्तुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सूक्ष्म अवलोकन करने से यह पता चलता है कि किस प्रकार यह नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति गुणवत्तापूर्ण, भारतीयता के बोध से युक्त शिक्षा का एक ठोस आधार देश के समक्ष रखती है, जिसके क्रियान्वयन से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक बदलाव हो सकता है| ध्यान दें तो नई शिक्षा नीति में प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक समस्त विषयों – सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, तार्किक, वैज्ञानिक, गणितीय, तकनीकी, भौगोलिक, पर्यावरणीय, आध्यात्मिक के साथ–साथ राष्ट्रीय भावना व राष्ट्रीयता का समावेश किया गया है| बहरहाल, इस नई नीति में भाषायी विविधता के संरक्षण को लेकर कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा अथवा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल देने के साथ–साथ इस शिक्षा नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव और स्कूली व उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होग, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। यह इस पहल इस बात का प्रमाण है कि सरकार भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' का निर्माण तथा छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' की स्थापना, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग जैसे अनेक नवाचार इसमें दिखाई देते हैं।

Image credit: Md. Bayzid Khondoker

नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर लिये गए कार्य-प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' का विकास, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा' को भी तरजीह दी गई है।

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान - NEP-2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा तथा NEP-2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्ज़िट व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' दिया जाएगा, जिससे अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग गठन किया जाएगा। इन समस्त विषयों का यदि सही रूप में अवलोकन किया जाये तो हम निस्संदेह इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि यह नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्वव्यापी बनाने में कारगर सिद्ध होगी।

लेखक: मिथिलेश कुमार पाण्डेय
पीएचडी शोध छात्र,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली.

Bhartiya Janata Yuva Morcha

BJYM